CEDSI TIMES

Your Skilling Partner...

तोमर पीएम-किसान, अन्य योजनाओं के लिए पात्र किसानों के डेटाबेस पर प्रगति की समीक्षा करेंगे

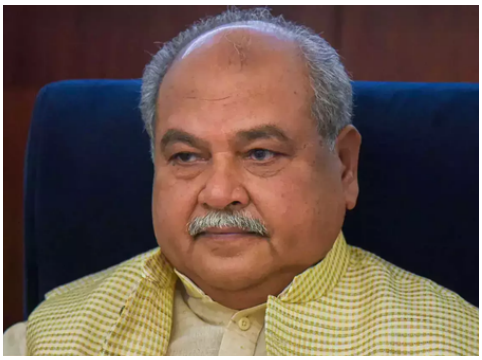

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम-किसान और अन्य योजनाओं के लिए पात्र किसानों की त्वरित पहचान के लिए बनाए जा रहे डेटाबेस पर काम की समीक्षा की।

तोमर ने राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में राज्यों से डाटा वेरिफिकेशन और अपडेट का काम जल्द से जल्द पूरा करने को कहा ताकि कोई भी पात्र किसान योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है, जो 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में देय होता है।

फरवरी 2019 में इसकी शुरुआत के बाद से, पीएम-किसान के तहत 11 किस्तों का वितरण किया गया है। इस योजना के माध्यम से लगभग 11.37 करोड़ पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हस्तांतरण किया गया है। पीएम-किसान का लाभ केवल भूमि जोत वाले किसानों को ही दिया जाता है।

राष्ट्रीय सहकारी नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए पैनल का गठन

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहयोग नीति दस्तावेज का मसौदा तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 47 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु करेंगे।

“समिति में सहकारी क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हैं; राष्ट्रीय / राज्य / जिला और प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधि; राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों की सहकारी समितियों के सचिव (सहकारिता) और रजिस्ट्रार; और केंद्रीय मंत्रालयों / विभागों के अधिकारी, ”मंत्रालय ने एक बयान में कहा।

"आज, भारत में लगभग 8.5 लाख सहकारी समितियां हैं, जिनके सदस्य आधार लगभग 29 करोड़ हैं, जो देश भर में फैले हुए हैं। 'सहकार से समृद्धि' की दृष्टि से नया राष्ट्रीय सहयोग नीति दस्तावेज तैयार किया जा रहा है।" एक बयान कहा।

प्रधानमंत्री 12 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन करेंगे

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ग्रेटर नोएडा में 'आईडीएफ वर्ल्ड डेयरी समिट 2022' का उद्घाटन करेंगे, जिसमें 50 देशों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने का कार्यक्रम है।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की।

उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात के मुख्यमंत्री भी 48 साल बाद भारत में होने वाले वैश्विक कार्यक्रम में शामिल होंगे। पिछली बार भारत ने 1974 में अंतर्राष्ट्रीय डेयरी कांग्रेस की मेजबानी की थी।

12 सितंबर से शुरू हो रहे इस कार्यक्रम की थीम 'पोषण और आजीविका के लिए डेयरी' है। डेयरी शिखर सम्मेलन वैश्विक और भारतीय डेयरी उद्योग के नेताओं, विशेषज्ञों, किसानों और नीति योजनाकारों का एक समूह है।

आंध्र सरकार 'आंध्र गोपुष्टि' बैनर के तहत देसी गाय के दूध उत्पादों को लॉन्च करेगी

राज्यसरकार पूरे आंध्र प्रदेशमें देशी गाय कीनस्लों के साथ-साथजैविक दूध उत्पादों केविकास को बढ़ावा देनेके लिए 'आंध्र गोपुष्टि' बैनर के तहत देसीगाय के दूध आधारितउत्पादों को लॉन्च करनेके लिए तैयार है।

इन उत्पादों के लिए पहला विशेष स्टाल सितंबर के तीसरे सप्ताह में विजयवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। जैविक दूध उत्पादों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विस्तार से बताते हुए, पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ आर अमरेंद्र कुमार ने कहा, "हम आंध्र गोपुष्टि ब्रांड नाम के तहत एक विशिष्ट बाजार को पूरा करने का लक्ष्य बना रहे हैं। जैविक उत्पाद स्वदेशी गाय की नस्लों द्वारा उत्पादित A2 दूध से बने होंगे।उन्हें प्रीमियम के रूप मेंवर्गीकृत किया जा सकताहै और इसलिए, उनकीकीमत उसी के अनुसारहोगी।"

उन्होंनेकहा कि इस तरहके उत्पादों की मांग ग्रामीणक्षेत्रों की तुलना मेंशहरों में अधिक है।यह कहते हुए किप्राथमिक उद्देश्य स्वदेशी गाय की नस्लोंजैसे ओंगोल, पुंगनूर, गिर, देवनी, राठीके विकास को बढ़ावा देनाहै, कुमार ने समझाया, "पहलेमें चरण, हमने छहमहीने पहले 58 देसी गाय फार्मस्थापित किए। दूसरे चरणमें ऐसे 28 और फार्म स्थापितकिए जाएंगे। 26 जिलों में से प्रत्येकमें तीन से पांचइकाइयां होंगी, जो कि कंपनीअधिनियम के तहत आंध्रगोपुष्टि किसान उत्पादक संगठन का हिस्सा हैं।

प्रत्येकफार्म को स्थापित करनेकी लागत 30 लाख रुपये है और सरकार ऐसी इकाइयों कोस्थापित करने वालों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है।

आंध्र प्रदेश: आरबीके को एक इकाई के रूप में लेकर यंत्र सेवा के तहत उपकरण वितरित करें, सीएम कहते हैं

मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने अधिकारियों को आंध्र प्रदेश में वाईएसआर यंत्र सेवा कार्यक्रम के तहत सभी रायथू भरोसा केंद्रों (आरबीके) में कृषि मशीनरी, उपकरण और उपकरण की उपलब्धता के लिए उपाय करने का निर्देश दिया।

आरबीके किसानों के लिए वास्तविक समय बाजार मूल्य जानने और ऑर्डर देने के लिए डिजिटल कियोस्क हैं। RBK सरकार द्वारा परीक्षण किए गए, पैक किए गए और ग्रेड किए गए उत्पादों को भी बेचता है।

जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वाईएसआर यंत्र सेवा से संबंधित डेटा को आरबीके में पोस्टर के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि किसान उपलब्धता और उपयोगिता को समझ सकें।

उन्होंने कहा कि आरबीके को एक इकाई के रूप में लेते हुए सभी उपकरणों का वितरण किया जाना चाहिए और कहा कि राज्य कार्यक्रम के लिए 910 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है। वह आरबीके के आसपास के क्षेत्र में खरीद केंद्रों, गोदामों और शीत भंडारण कक्षों के निर्माण में तेजी लाना चाहते थे।

चेयुथा कार्यक्रम के तहत सतत आर्थिक विकास के लिए स्वयं सहायता योजनाओं को जारी रखा जाना चाहिए। मवेशियों के वितरण से दूध उत्पादन और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा।

सरकारी योजनाओं के तहत पशुपालकों को सुनिश्चित करें: केंद्र से राज्यों तक

केंद्र सरकार ने स्वीकार किया कि विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित होने की बात आने पर भारत के पशुचारक समुदाय दरार से गिर गए। इसने ऐसे समुदायों की बड़ी आबादी वाले राज्यों से इसे रोकने के लिए काम करने का आग्रह किया है।

भारत भर में चरवाहों या पशुपालकों की एक महत्वपूर्ण आबादी है जो अपने जानवरों को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कोई आधिकारिक संख्या नहीं है, लेकिन चरवाहों के साथ काम करने वाले संगठनों के अनुसार, भारत के जंगलों और घास के मैदानों में क्रमश: लगभग एक करोड़ और दो करोड़ चरवाहे चरते हैं।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने 23 अगस्त, 2022 को विभिन्न राज्य पशुपालन विभागों को एक पत्र लिखा था। पत्र में राज्यों को राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालन अवसंरचना विकास कोष (एएचआईडीएफ) और राष्ट्रीय गोकुल मिशन (मवेशियों के लिए) के तहत पशुपालकों को सहायता प्रदान करने को कहा गया है।

अब तक, पशुधन से संबंधित योजनाएँ ज्यादातर किसानों और पशुपालकों की बसी हुई आबादी की पूर्ति करती थीं। पशुपालकों को सैद्धांतिक रूप से योजनाओं से बाहर नहीं रखा गया है, लेकिन विनियमन दस्तावेज विशेष रूप से समुदाय का उल्लेख नहीं करते हैं।

केंद्र सरकार ने पत्र में राज्यों से डेयरी और मांस प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना और प्रबंधन के लिए एक किसान-उत्पादक संगठन या देहाती समुदाय के सदस्यों के सहकारी की संभावना पर गौर करने को कहा है।

कृषि मंत्रालय और फिक्की की संयुक्त पहल कृषि में पीपीपी परियोजनाओं को आकर्षित करने के लिए शुरू की गई

केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में कृषि में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) का शुभारंभ किया। इस अवसर पर बोलते हुए, तोमर ने कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया क्योंकि इससे अन्य क्षेत्रों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

तोमर ने कहा कि व्यापार और उद्योग क्षेत्र मजबूत और सुव्यवस्थित है और उनके पास कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक सभी संसाधन हैं। सरकार, अपने हिस्से के लिए, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चल रहे कदम उठा रही है जैसे कि कृषि अवसंरचना कोष रु। एक लाख करोड़, 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।

फिक्की के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शुभकांत पांडा ने विश्वास व्यक्त किया कि कृषि में पीपीपी के लिए पीएमयू पहल, जो आज शुरू की गई थी, निजी क्षेत्र के निवेश का लाभ उठाकर और सरकारी योजनाओं और सब्सिडी को एक साथ लाकर कृषि में बड़े पैमाने पर पीपीपी परियोजनाओं को गति देगी।

शुभकांत पांडा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एफ आई सीसीआई (फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) ने विश्वास व्यक्त किया कि कृषि में पीपीपी के लिए पीएमयू पहल, निजी क्षेत्र के निवेश का लाभ उठाकर और सरकारी योजनाओं और सब्सिडी लाकर कृषि में बड़े पैमाने पर पीपीपी परियोजनाओं को गति देगी। आपस में नजदीक।

लंपी त्वचा रोग: केंद्र ने राज्यों को टीकाकरण में तेजी लाने के लिए कहा क्योंकि 57,000 मवेशी मर जाते हैं

केंद्र ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में ' लंपी त्वचा रोग' के कारण अब तक लगभग 57,000 मवेशियों की मौत हो चुकी है और प्रभावित राज्यों से इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए टीकाकरण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए कहा है।

लंपी त्वचा रोग (एलएसडी) एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो मवेशियों को प्रभावित करती है और बुखार, त्वचा पर गांठ का कारण बनती है और इससे मृत्यु भी हो सकती है।

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, "गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित 6-7 राज्यों में ढेलेदार त्वचा रोग फैल गया है, कुछ मामले सामने आए हैं।"

रूपाला ने कहा कि उन्होंने स्थिति का आकलन करने और नियंत्रण कार्यों की निगरानी के लिए पांच राज्यों का दौरा किया है। मंत्रालय रोजाना स्थिति पर नजर रखे हुए है। मंत्री ने जोर देकर कहा कि 'गोआट पॉक्स वैक्सीन' बहुत प्रभावी और उपलब्ध है, और राज्य सरकारों से टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कहा।

मंत्री ने कहा कि अभी तक दूध उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ा है। रूपाला ने कहा कि टीकाकरण में वृद्धि और बीमारी को नियंत्रित और नियंत्रित करने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करके बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। मंत्री ने राज्यों से मृत मवेशियों को दफनाने के प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा।

लंपी त्वचा रोग: योगी सरकार वायरस की जांच के लिए मलेशियाई मॉडल अपनाएगी

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जानवरों के बीच लंपी त्वचा वायरस की बीमारी को रोकने के उद्देश्य से पांच जिलों के 23 ब्लॉकों से गुजरने वाले पीलीभीत और इटावा के बीच 300 किमी लंबी और 10 किमी चौड़ी 'इम्यून बेल्ट' की योजना बनाई है। प्रतिरक्षा बेल्ट वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक क्षेत्र का निर्माण है।

अब तक राज्य के 2,331 गांवों की 21,619 गायें लम्पी वायरस की चपेट में आ चुकी हैं, जिनमें से 199 की मौत हो चुकी है, जबकि 9,834 का इलाज किया जा चुका है और वे ठीक हो चुकी हैं। जानलेवा वायरस पर काबू पाने के लिए योगी सरकार बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चला रही है. अब तक 5,83,600 से अधिक मवेशियों का टीकाकरण किया जा चुका है।

पशुपालन विभाग द्वारा इम्यून बेल्ट के तहत निगरानी के लिए विशेष प्रवर्तन दल का गठन किया जाएगा। टास्क फोर्स लम्पी वायरस से संक्रमित जानवरों की ट्रैकिंग और इलाज का काम संभालेगी। इससे पहले 2020 में भी मलेशिया में जानवरों के संक्रमण को रोकने के लिए इसी तरह का प्रयास किया जा चुका है, जिसके परिणाम बेहद सकारात्मक रहे हैं।

ऑर्गेनिक डेयरी स्टार्टअप अक्षयकल्प ऑर्गेनिक ने फंडिंग में $15 मिलियन जुटाए

ऑर्गेनिक डेयरी स्टार्टअप अक्षयकल्प ऑर्गेनिक ने कहा कि उसने ग्रोथ के लिए निवेशकों से 1.5 करोड़ डॉलर (करीब 120 करोड़ रुपये) जुटाए हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा, ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, यूके की विकास वित्त संस्था, रेनमैटर फाउंडेशन और इसके मौजूदा निवेशक वेंचर डेयरी सीरीज बी फंडिंग राउंड में शामिल हो गए हैं।

जीएनएस रेड्डी और शशि कुमार द्वारा स्थापित, अक्षयकल्प ऑर्गेनिक देश में अग्रणी जैविक दूध उत्पादकों में से एक है। अक्षयकल्प की योजना बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के बाजारों में आक्रामक रूप से निवेश करने की है। यह पुणे, मुंबई और कोच्चि के नए भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार करने और अपने डेयरी उत्पादों को पूरे भारत में ले जाने की योजना बना रहा है।

यह वर्तमान में 750 से अधिक किसान परिवारों के साथ काम करता है। यह अपने डायरेक्ट डिलीवरी प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में रोजाना 60,000+ उपभोक्ताओं को जैविक दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति करता है। इसके उत्पाद 2,000 रिटेल आउटलेट्स और सभी प्रमुख ई-कॉमर्स/क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं।

"पिछले कुछ वर्षों में, उपभोक्ता स्वस्थ जीवन शैली जीने के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं। ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, रेनमैटर और वेंचर डेयरी के समर्थन से, हम अपने उत्पादों की गुणवत्ता को बरकरार रखने की उम्मीद करते हैं। अक्षयकल्प ऑर्गेनिक के सह-संस्थापक और सीईओ शशि ने कहा, "हम स्थायी कृषि प्रणाली बनाने और ग्रामीण भारत की गरिमा बहाल करने के अपने प्रयासों को गहरा करते हुए अधिक ग्राहकों की सेवा करना जारी रखेंगे।"

भोपाल में कृषि यंत्रीकरण में सीओई की स्थापना के लिए एएससीआई ने डीएजीई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारतीय कृषि कौशल परिषद (एएससीआई) - कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यरत कृषि पर क्षेत्र कौशल परिषद ने माननीय कृषि मंत्री की उपस्थिति में कृषि इंजीनियरिंग निदेशालय (डीएजीई) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। , मध्य प्रदेश, श्री कमल पटेल। कृषि और कृषि मशीनीकरण मूल्य श्रृंखला में किसानों, मजदूरी श्रमिकों और अन्य हितधारकों को सशक्त बनाने के लिए फार्म मशीनीकरण के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीईएफएसआई) की स्थापना की जा रही है। सीईएफएसआई एक ऐसा संस्थान होगा जो नेतृत्व प्रदान करेगा, सर्वोत्तम प्रथाओं की स्थापना करेगा, कृषि मशीनीकरण क्षेत्र के विकास पर अनुसंधान करेगा और प्रौद्योगिकी परिवर्तनों के लिए नई कौशल आवश्यकताओं को संशोधित करेगा, कृषि मशीनीकरण क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा, और वकालत और सलाहकार सेवाएं प्रदान करेगा।

प्रस्तावित संस्थान क्षेत्र की आगामी भविष्य की जरूरतों के लिए ज्ञान प्रबंधन, कौशल और क्षमता निर्माण, और उच्च गुणवत्ता और विशेष कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के वितरण में नेतृत्व करेगा। केंद्र घनिष्ठ संबंध बनाए रखेगा और सरकार, उद्योग, अनुसंधान और शिक्षाविदों और कृषि मशीनीकरण क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करेगा।

डेयरी और सतत विकास लक्ष्य

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेयरी स्किल्स इन इंडिया (सीईडीएसआई) डेयरी और संबद्ध क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला में किसानों, मजदूरी श्रमिकों और अन्य हितधारकों के लिए आजीविका के सशक्तिकरण और बेहतरी में मदद करता है। हमने यह पहल सभी हितधारकों को जागरूक करने के लिए की है कि कैसे डेयरी क्षेत्र में काम करने से वास्तविक बदलाव आएगा। हर हफ्ते हम प्रकाशित करेंगे कि कैसे प्रत्येक लक्ष्य डेयरी और पशुधन से जुड़ा है और सभी के लिए समग्र सतत विकास ला रहा है।

लक्ष्य 1: कोई गरीबी नहीं

सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के एजेंडा (एसडीजी 1) का लक्ष्य 1 गरीबी को उसके सभी रूपों में समाप्त करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण लेता है। एसडीजी 1 लक्ष्य

1) अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन
2) गरीबों के बीच लचीलापन बनाना
3) ध्वनि नीति ढांचे का निर्माण

एसडीजी लक्ष्य 1 के लिए डेयरी/पशुधन सही भागीदार

गरीब परिवारों को उनकी आजीविका के स्तर को बनाए रखने में मदद करने में पशुधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फसलों और गैर-कृषि रोजगार के बाद पशुधन गतिविधियां आय का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ग्रामीण परिवारों को उनकी आजीविका के उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करने में पशुधन उत्प्रेरक है, उनमें से कुछ हैं:

- गतिविधियों की खोज के लिए भोजन, निरंतर अच्छे स्वास्थ्य और श्रम तक पहुंच प्रदान करके मानव पूंजी में वृद्धि करें
- सामाजिक पूंजी का निर्माण, कई जातीय समूहों और आबादी की सांस्कृतिक विविधता और विरासत को मजबूत करना
- प्राकृतिक पूंजी के भंडार में योगदान करें जो आजीविका को बनाए रखने और सुधारने के लिए आवश्यक संसाधन और सेवाएं प्रदान करता है
- भौतिक पूंजी में वृद्धि, परिवारों को उनकी उत्पादकता को समर्थन देने और सुधारने के लिए परिवहन, मसौदा शक्ति और वैकल्पिक ऊर्जा प्रदान करना
- आजीविका लक्ष्यों को हासिल करने के लिए परिवारों की वित्तीय पूंजी में वृद्धि, बचत के लिए एक तंत्र प्रदान करना, और तरल संपत्ति के रूप में या ऋण संपार्श्विक के रूप में कार्य करना
- बाहरी झटकों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में कार्य करें

इस प्रकार पशुधन ग्रामीण परिवारों के आर्थिक विभागों में आय विविधीकरण के स्रोत के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। पशुधन गतिविधियों, आय विविधीकरण और गरीबी में कमी के बीच संबंध सीधा नहीं है। डायरी विकास की प्रमुख चुनौती डेटा की अनुपलब्धता और डेटा की गुणवत्ता भी है। अक्सर कृषि या घरेलू सर्वेक्षणों में उपलब्ध सांख्यिकीय जानकारी किसी को घरेलू आजीविका रणनीतियों में विभिन्न पशुधन गतिविधियों के बीच अंतर करने की अनुमति नहीं देती है। आय में सुधार के लिए डेयरी क्षेत्र के संबंध का विपरीत हिस्सा अभी भी अनिर्णायक है। एकत्र किए गए प्राथमिक डेटा की कमी अक्सर अपर्याप्त विश्लेषण की ओर ले जाती है। पशुधन अपने आप में एक अकेली इकाई या गरीबी को कम करने वाला चालक नहीं है, बल्कि यह अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ समामेलन में काम करता है, क्योंकि पशुधन और आय के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। पशुधन के योगदान को गरीब लोगों को उनके आजीविका लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने में उनकी उत्प्रेरक भूमिका के आलोक में समझा जाना चाहिए। पशुधन और गरीबी के बीच संबंधों को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए, आय सृजन में पशुधन उत्पादन के योगदान को आय के अन्य कृषि और गैर-कृषि स्रोतों से अलग नहीं किया जाना चाहिए। वे सभी लचीलापन बनाने और गरीबी से लड़ने के लिए ग्रामीण परिवारों द्वारा नियोजित जटिल आजीविका रणनीतियों का हिस्सा हैं।

आजीविका प्रबंधन में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और, जलवायु के झटके और अन्य प्रकार के बहिर्जात आय-घटाने वाले संकटों से निपटना गरीब, अकुशल परिवारों के लिए बेहद कठिन हो सकता है और इससे दुख और अनिश्चितता बढ़ सकती है। ये कठिनाइयाँ तब और बढ़ जाती हैं जब एक ही समुदाय के सभी सदस्यों को एक साथ झटके लगते हैं, जैसा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जलवायु झटकों के मामले में होता है। बाहरी जलवायु आघात के खिलाफ लचीलापन बनाने में पशुधन की भूमिका को एहतियाती रूप में देखा जा सकता है। सबसे अच्छा अभ्यास एक एकीकृत खेत है जिसमें फसलों और पशुधन दोनों का स्वामित्व इन झटकों के प्रति अधिक लचीला होता है।

उपसंहार

एसडीजी 1 गरीबी को समाप्त करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण का आह्वान करता है। पशुधन वास्तव में उन परिसंपत्तियों को मजबूत करने में एक उत्प्रेरक भूमिका निभा सकता है जिनका उपयोग ग्रामीण परिवार अपने आजीविका के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं, और परिवारों के बाहरी झटकों के लिए लचीलापन बढ़ाने में।

एसडीजी लक्ष्यों के साथ संरेखण में सामाजिक विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए सीईडीएसआई के साथ भागीदार।

Centre of Excellence for Dairy Skills in India

Join Our Membership Drive and Get Benefits of

- Platform to interact with other members in the sector
- Networking opportunities with corporate leaders and government authorities
- Special costs of training in Skill India Certified Programmes
- Access to our Journal and Publications
- Expert advice in day-to-day operations and management of livestock /farm productions
- Free registration on the job portal and regular updates on job vacancies in the sector
- Recognize your organization with CEDSI Yearly Awards and Recognition
- Chance to reach across the board through advertising in our press releases, news and articles
- Consultative and advisory services to help members
- Consulting and advisory services to help members
- Periodic e-newsletter for the latest news, govt. announcement and schemes in dairy sectors
- Updates on training programs of CEDSI and access to the training calendar

Who Can Become a Member -

Corporates/ Cooperatives

NGO's/CSR Foundations

Dairy Farmers

Students

Professional

www.cedsi.in @cedsi_india